BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार विक्रम संवत् 2079। 04 जून 2022

JKDESIGN 8369994118

नई टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी 8 को लॉन्च होगी : शाहनवाज

पटना के अधिवेशन भवन में सीएम करेंगे शुरुआत

भास्कर न्यूज | भागलपुर

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि बिहार सरकार 8 जून को नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च करेगी। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। उस दिन टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का भी आयोजन होगा। पॉलिसी कैबिनेट से पास हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि बिहार देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जो इस पॉलिसी को लेकर आनेवाला है। इसके तहत 10 करोड़ तक के कैपिटल सब्सिडी का लाभ उद्योग लगाने वालों को मिलेगा। बैंकों से लिए गए लोन का ब्याज भी सरकार ही चुकाएगी। इस उद्योग में काम करनेवाले कर्मचारियों को अगर मालिक से दस हजार रुपए मिलेंगे तो पांच हजार रुपए सरकार भी अपनी ओर से देगी। यानी की उद्योग लगाने वालों से लेकर उसमें काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए भी यह लाभदायक योजना सिद्ध होगी। इसके लिए सरकार ने गंजी-जांघिया बनाने वाली ब्रांडेड कंपनियों को न्योता दिया है। मंत्री ने बिहार से बनारस व अन्य जगह गए बुनकरों से भी वापस लौटने की अपील की है।

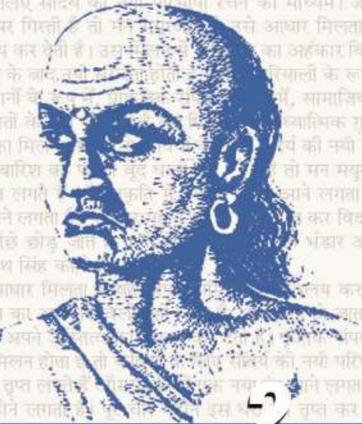

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 04.06.2022 | पृष्ठ सं० 08

उद्यमिता व स्टार्टअप का हुनर सीखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राएं

- आईआईटी रूड़की के सहयोग से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिलेगा प्रशिक्षण
- पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थी उद्यमिता और स्टार्टअप का भी हुनर सीखेंगे। उन्हें उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास बेहतर रोजगार उपलब्ध हो। अपना रोजगार शुरू करने में भी उन्हें मदद मिले। आईआईटी रूड़की की मदद से विद्यार्थियों को यह विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के साथ आईआईटी रूड़की का करार हुआ है।

आईआईटी रूड़की जल्द ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। जिन विषयों का प्रशिक्षण छात्र-छात्राओं को दिया जाना है, उनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख हैं। इस प्रशिक्षण का एक मकसद स्टार्टअप के लिए मानव संसाधन विकसित करना भी है।

आईआईटी रूड़की द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी पटना के साथ करार हुआ है। इस तरह राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक में और बाजार की मांग के अनुरूप दक्ष बनाया जाएगा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत राज्य में 38 इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय का भी गठन किया गया है। इस विश्वविद्यालय के अधीन सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे। विश्वविद्यालय का संचालन शुरू करने के लिए कुलपति समेत अन्य पदों का सृजन किया जा चुका है। जल्द ही इन सभी की नियुक्ति किये जाने की उम्मीद है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 04.06.2022 | पृष्ठ सं० 06

समीक्षा बैठक • बिहार के सभी जिलों में आहार-पईन की सफाई की जाएगी

जल-जीवन-हरियाली और खेत तक पानी पहुंचाने की योजना से समस्याएं होंगी दूर

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

योजना विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान योजना विकास विभाग के मंत्री और योजना पर्षद के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही सिचाई के लिए खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही पानी के संचय की भी व्यवस्था होगी। जिससे गर्मियों में पानी की समस्या का निस्तारण हो सके। इसके लिए बनायी गई सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। जिसके तहत जिन जगहों पर योजनाएं लागू नहीं हुई है, वहां पर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 जिलों में 2019-20 में 1791 सिंचाई और जल संचयन के लिए योजना शुरू की गई थी। जिसमें 1469 योजनाएं पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही साढ़े सात सौ घन मीटर पानी संचयन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों में स्थित पइन, आहार की सफाई की जाएगी। जिससे अधिक से अधिक जगहों पर सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके। योजना विकास विभाग के मंत्री और योजना पर्षद के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बंद सरकारी नलकूपों को शुरू किया जाएगा। एक साल पुरानी योजना होने के बाद भी 2021-22 में प्रदेश में 557 नलकूपों को शुरू किया गया है। जिसके तहत 18.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही पठारी क्षेत्रों में भी पानी के संचय के लिए काम किया जा रहा है। जिसके तहत गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके।

मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : उपमुख्यमंत्री

पटना में नमामि गंगे द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम" में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए और अपने विचार रखे। इस दौरान गंगा नदी में छोटी मछलियों को भी डाला गया।

पटना | पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बामेती परिसर में आयोजित तीन दिवसीय नवनियुक्त मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन मौके पर उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मत्स्य पालन और पशुपालन का क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मत्स्य पालन का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि अपने संबंधित क्षेत्रों में परिश्रम, लगन, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ अपने कार्यों और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें

नदियों में सालोंभर पानी, मछली उत्पादन की बड़ी संभावनाएं

डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया है। बिहार राज्य में फीड मील की स्थापना, अर्द्रभूमि की विकास हेतु चौर विकास योजना, रियरिंग एवं नए तालाब का निर्माण, नई तकनीक बायो फ्लॉक, ब्रुड बैंक की स्थापना, मांगुर हैचरी, मीठा जल झींगा हैचरी, डायग्नोस्टिक रेफरल लैब की फतुहा में स्थापना, किशनगंज में कॉलेज ऑफ फिशरीज की स्थापना होने से मत्स्य की प्रसिद्ध में उत्तरोत्तर प्रगति आयी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल संपदा प्रचुर मात्रा में है। गंगा, कोसी, बागमती, गंडक जैसी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जहां सालों भर पानी की प्रचुरता रहती है। ऐसी स्थिति में राज्य में मछली उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। मत्स्य निदेशालय द्वारा 126 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर 120 नवनियुक्त मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को उप मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉ एन सरवन कुमार, बामेती के निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार, मत्स्य निदेशक निशात अहमद, दिलीप कुमार सिंह, राशिद फारूकी, पवन कुमार पासवान, उमेश रंजन, सुमन कुमार सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 04.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एयरपोर्ट निदेशक ने की बैठक

पटना एयरपोर्ट का दिसंबर 2023 तक निर्माण होगा पूरा, रनवे की बढ़ेगी लंबाई

सिटी रिपोर्टर | पटना

पटना एयरपोर्ट का दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा होगा। इसके साथ ही रनवे की लंबाई बढ़ेगी। एयरपोर्ट के निदेशक अंचल प्रकाश ने कहा कि बिहार एयरपोर्ट के निर्माण में कुछ मामले आए हैं। इसके क्लीयरेंस का इंतजार हो रहा है। न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट पर कार्य अगले डेढ़ साल में पूरा होगा। इससे पहले कार्गो भवन का निर्माण कार्य अगले छह महीने में पूरा करने का टास्क दिया गया है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्री सुविधाएं और बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के प्रवेश गेट पर वरीय नागरिकों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ताकि, बुजुर्गों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं, एयरक्राफ्ट में गंगा जल लेकर जाने के लिए पहले से निर्धारित वजन बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। वे शुक्रवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित बैठक के दौरान व्यवसायियों को संबोधित कर रहे थे।

11 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा, यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग

एयरपोर्ट निर्देशक ने कहा कि लीची का एक्सपोर्ट करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इसका सीधा लाभ किसानों और व्यवसायियों को मिलेगा। इससे पहले चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने एयर यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाए जाने की मांग की। चैंबर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने एयरपोर्ट निदेशक को 11 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एयरपोर्ट के संयुक्त महाप्रबंधक एके पाठक, अरविन्द पासवान, उप महाप्रबंधक संतोष कुमार, ओम प्रकाश, कमांडेट एके झा, इंडिगो एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर कुरैशी हसन, स्पाइसजेट के सैयद जेड हसन, एयर इंडिया के अमर सहाय, चैंबर के महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल सहित अन्य वरीय सदस्य सदस्य उपस्थित थे।

दिल्ली-मुंबई की तरह सभी मौसम में विमान लैंडिंग की सुविधा हो

दिल्ली और मुंबई की तरह सभी मौसम में विमान लैंडिंग की सुविधा बहाल करने, सुरक्षा जांच में प्रत्येक ट्रे के लिए दो टोकन का प्रावधान करने, दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सुविधा बहाल करने, भीड़भाड़ वाले समय में पीक और ड्रॉप का समय बढ़ाने, सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर और काउन्टर की संख्या को बढ़ाने, खान-पीने की सामग्री बाजार दर पर उपलब्ध कराने, चेक इन टाइम को कम करने, उड़ान योजना के तहत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, समस्तीपुर, गया, आरा, मोतिहारी के एयरपोर्ट का समुचित विकास करने आदि की मांग रखी गई।

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 04.06.2022 | पृष्ठ सं० 04

केंद्र सरकार ने हर महीने के लिए तय किया उर्वरक का कोटा

खरीफ : बिहार को 17 लाख टन खाद मिलेगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में खरीफ की खेती के लिए केन्द्र की ओर से लगभग 17 लाख टन खाद मिलेगी। केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए खाद का आवंटन कर दिया है। आवंटन के अनुसार आपूर्ति बहाल रही तो इस बार खरीफ में खाद की किल्लत नहीं होगी। ऐसे आपूर्ति की वर्तमान स्थिति देखने से लगता है कि केन्द्र बिहार के साथ अनदेखी नहीं करेगा। अप्रैल और मई के लिए जितना आवंटन था उसका 140 प्रतिशत खाद बिहार में पहुंच गई। यानी आवंटन से लगभग ड्योढ़ा।

केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए जो कोटा तय किया है उसके अनुसार सबसे अधिक 10 टन यूरिया का आवंटन मिला है। तीन लाख टन डीएपी और एक लाख टन एसएसपी खाद राज्य को मिलेगी। इसके अलावा एमओपी एक लाख टन और एनपीके दो लाख टन केन्द्र बिहार को देगा। जरूरत के अनुसार देखें तो अप्रैल और मई के लिए 60-60 हजार टन यूरिया का आवंटन है। जून में एक लाख बीस हजार टन और जुलाई में एक लाख टन का आवंटन है। सबसे अधिक दो लाख 80 हजार टन अगस्त में मिला है। उस समय फसल की सिंचाई के बाद खाद की जबरदस्त मांग बढ़ती है। इसी प्रकार दूसरी खाद का भी आवंटन जरूरत के अनुसार मिला है।

खाद की खपत बढ़ी: राज्य में पांच साल पहले खाद की खपत जहां 160 किलो प्रति हेक्टेयर थी, वहीं अब यह बढ़कर 207 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। तीन साल पहले भी खपत 201 किलो प्रति हेक्टेयर ही थी। केन्द्र ने इसी का ख्याल कर आवंटन तय किया है। हालांकि रबी में खाद की ज्यादा लगभग ड्योढ़ा उपयोग होता है। गत वर्ष खरीफ और रबी मिलाकर 22.88 लाख टन यूरिया खाद का उपयोग किसानों ने किया था। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 21.83 लाख टन का था। यानी तीन साल में यूरिया की खपत राज्य में एक लाख टन बढ़ गई। इस साल भी दस हजार टन अधिक आवंटन है।

यूरिया की खपत में रोहतास आगे: यूरिया की खपत में रोहतास जिला सबसे आगे है तो फास्फेटिक खादों के उपयोग में पूर्णिया। रोहतास में 1.14 लाख टन यूरिया की खपत होती है। पूर्णिया में एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) की खपत 1.09 लाख टन है। हालांकि यूरिया के उपयोग में भी पूर्णिया का दूसरा और पूर्वी चम्पारण का तीसरा नम्बर है।

03 लाख टन डीएपी की आपूर्ति होगी राज्य को

10 लाख टन यूरिया खाद का मिला है आवंटन

02 लाख टन एनपीके व एक लाख टन मिलेगी एमओपी

01 लाख टन एसएसपी खाद का भी होगा आवंटन

कृषि विभाग ने अफसरों को सतर्क किया

आवंटन मिलते ही कृषि विभाग ने अपने अफसरों को सतर्क कर दिया है। मुख्यालय के अफसरों को आवंटन के अनुसार आपूर्ति पर नजर रखने को कहा गया है, ताकि ऐसा नहीं हो कि जून का आवंटन अगस्त में मिले। मगर अगस्त में सरकार ने आपूर्ति ठीक रखी तो मारामारी नहीं होगी, वरना कालाबाजारियों की पौ बारह हो जाती है।

यूरिया की जरूरत 1.20 लाख टन, आपूर्ति 1.67 लाख टन

अप्रैल व मई की बात करें तो इन दो महीनों में यूरिया खाद की जरूरत बिहार को 1.20 लाख टन की थी। मगर आवंटन 1.30 लाख टन का है और आपूर्ति मिली है 1.67 लाख टन। दूसरी खादों की स्थिति भी ऐसी ही है।

पिछले वर्ष आवंटन से एक लाख टन खाद कम मिली थी

गत वर्ष आवंटन से एक लाख टन खाद कम मिली थी। आयात नहीं होने से ऐसा हुआ। लिहाजा राज्य सरकार के लाख प्रयास के बाद भी खाद की कमी बनी रही और कालाबाजारियो ने किसानों को खूब ठगा।

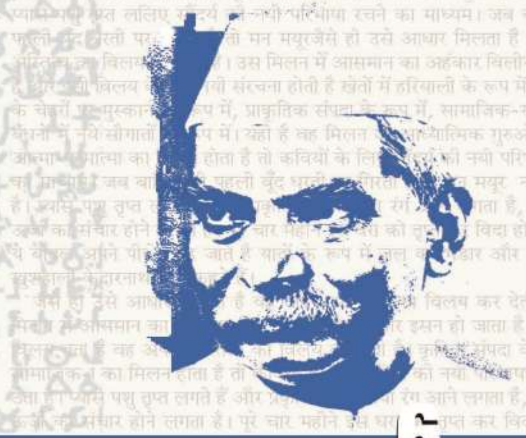

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	53
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	15
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	3
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,27,24,875
⇒ कम से कम एक डोस	7,07,57,443
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,00,89,236

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

विदेश अवस्थित चैप्टर

- कतर
- दक्षिण कोरिया
- जापान
- हॉग कॉग
- यू.ए.ई.
- सिंगापुर
- बहरीन
- न्यूजीलैंड
- कनाडा
- यू.एस.ए.
- ऑस्ट्रेलिया
- सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई	हैदराबाद	पुणे
चेन्नई	नागपुर	गुजरात
कोलकाता	वाराणसी	गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.